www.maadurgawallpaper.com
Happy
Basant
Panchami

खबरें फटाफट

विदेश

- भारतीय सीमा पर चीन ने नीति बदली, कंट्रोल सीधा सेना के हाथ में
- चैक रिफाइनरी में विस्फोट, 6 मरे, कई घायल
- 'पाकिस्तान में सभी राजनयिक सुरक्षित'
- फिलीपींसः 13 नशे के तस्कर ढेर, 100 गिरफ्तार
- मालद्वीवः 45 दिन बाद आपातकाल समाप्त

खेल

- टेनिस मियामी ओपनः ओसाका ने सेरेना को पहले ही दौर में किया बाहर
- ऑकलैंडः बोल्ट के करंट से इंग्लैंड 58 पर ढेर
- महिला क्रिकेटः आस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को फिर पीटा
- शमी को फिक्सिंग से क्लीन चिट, 'बी' ग्रेड करार मिला

व्यापार

- सेंसेक्स 129.91 अंक और निफ्टी 40.50 अंक लुढ़का
- दिल्लीः खाद्य तेलों में टिकाव, चना दाल, चीनी नरम, चना मजबूत
- दिल्लीः सोना 150 रु., चांदी 500 रु. चमके
- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत
- मोबाइल ऐप से ऑन-ऑफ कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड
- ज्ञान आधारित उद्योगों के लिये केरल सर्वोत्तम
- आरकॉम सम्पत्ति बिक्री मामलाः यथास्थिति बनाये रखने का आदेश
- फेड ने बढ़ाई ब्याज दर, दिये अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत

आज का इतिहास

नयी दिल्ली। भारतीय एवं विश्व इतिहास में 23 मार्च की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं-

1357 : लार्ड क्लाइव ने फ्रांसीसियों को हराकर पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर पर कब्जा किया।

1630 : फ्रांस की सेना ने पिनेरोलो पिडमाउंट पर कब्जा किया।

1832 : ब्रिटेन की संसद में सुधार विधेयक पारित किया गया।

1836 : फ्रेंकलिन बेल ने सिक्के छपाई के प्रेस का आविष्कार किया।

1910 : स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्म।

1918 : यूरोपीय देश लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की।

1919 : बेनिटो मुसोलिनी ने इटली के मिलान में फासिस्ट आंदोलन की शुरुआत की।

1931 : महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गयी।

1934 : अमेरिकी कांग्रेस ने 1945 में फिलीपींस की स्वतंत्रता को मान्यता दी।

1940 : ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की।

1950 : संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की।

1956 : पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र देश बना।

1965 : नासा ने पहली बार जैमिनी तीन अंतरिक्ष यान से दो व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा।

1986 : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को प्रशिक्षित किया गया।

2012 : मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने।

2014 : अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाए।

सरकारी अध्यापकों के बच्चे निजी स्कूलों में क्यों?

उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के केवल तेरह फीसद बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और बाकी के सत्तासी प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। सवाल है कि जिन शिक्षकों की जिम्मेदारी है सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ाना, उसी नौकरी से उनका परिवार पलता है, उसमें पढ़ाई का स्तर ऐसा क्यों है कि वे खुद वहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? - जीनत

मेरी ही तरह सरकारी स्कूल से पढ़े एक दोस्त ने स्कूल के दिनों का अनुभव साझा किया। वह जब बारहवीं कक्षा में था, तब पहली बार एक अध्यापक ने स्कूल से अंतिम कक्षा की पढ़ाई पूरी करके निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए 'फेयरवेल पार्टी' यानी विदाई समारोह आयोजित करने बात कही तो दूसरे अध्यापक ने उनके इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और यह टिप्पणी की कि सरकारी स्कूल के बच्चों में संस्कार नहीं होते हैं, इनके लिए पार्टी का आयोजन क्यों किया जाए!

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने वाले किसी शिक्षक के मन में आखिर ऐसे खयाल कहां से आते हैं? अगर कहीं ऐसा है भी तो इसके लिए 'दोषी' बच्चे हैं या अध्यापक या फिर कोई और? किसी बच्चे के भीतर 'संस्कार' कहां-कहां से आते हैं और उन संस्कारों के लिए समाज के कौन-से हिस्से जिम्मेदार हैं? सन् 2011 में तमिलनाडु में चंद्रशेखरन नामक व्यक्ति ने राज्य सरकार से सूचना के अधिकार कानून के तहत एक जानकारी मांगी थी। उसके जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के सत्ताईस प्रतिशत बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं; बाकी बचे तिहत्तर फीसद बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के केवल तेरह फीसद बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और बाकी के सत्तासी प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। सवाल है कि जिन शिक्षकों की जिम्मेदारी है सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ाना, उसी नौकरी से उनका परिवार पलता है, उसमें पढ़ाई का स्तर ऐसा क्यों है कि वे खुद वहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भीतर 'संस्कार' की खोज करने वाले शिक्षकों या सरकार की नैतिकता यहां किस तरह परिभाषित होगी? जिस दौर में मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, तब एक शिक्षक थे, जिन्हें शायद ही कभी किसी कक्षा में पढ़ाने जाते देखा गया था। वे स्कूल में अकसर बच्चों से कई तरह के काम करवाते थे।

हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एक खराब डॉक्टर एक मरीज की जिंदगी खराब कर देता है, पर जब एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी नहीं बरतता है तो वह पूरी पीढ़ी को खराब कर देता है। फिलहाल मैं एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पढ़ती हूं। वहां से लेकर अनेक स्कूलों तक के संदर्भ में देखती हूं तो लगता है कि कई ऐसे भी हैं, जिन्हें एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। खासतौर पर प्रशिक्षण के दौरान न केवल शिक्षण के तौर-तरीके सीखकर प्रयोगधर्मी शिक्षक बनना, बल्कि पहले से चले आ रहे सामाजिक पूर्वग्रहों से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब कई शिक्षकों को सामाजिक-धार्मिक जड़ताओं को सही ठहराते देखती हूं तो लगता है कि वे स्कूलों में बच्चों के मानस को क्या दिशा देंगे।

ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों ने शिक्षण के पेशे को महज सरकारी नौकरी की सुविधा का ठौर मान लिया है। जबकि सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी इसलिए है कि वहां आने वाले ज्यादातर बच्चे कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और अभावों के बीच उनकी शैक्षिक जमीन बहुत मजबूत नहीं हो पाती है। लेकिन सार्वजनिक शिक्षा या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई के बदतर होते हालात के लिए अकेले शिक्षकों पर अंगुली उठाना शायद समस्या को छोटा करना हो सकता है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कक्षाओं में पढ़ाने के अलावा कितने कामों में लगाकर रखा जाता है, क्या यह कोई छिपी बात है? ऐसे में कोई शिक्षक अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी बरतना भी चाहे तो किस स्तर तक वह ऐसा कर सकता है? 'शिक्षा का अधिकार कानून' लागू हुए कई साल हो गए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत आज भी क्या है और हमारे देश के बच्चों को यह कितना प्रभावी रूप में मिल पाया है? इस अधिकार के नाम पर ज्यादा दाखिले और स्कूल की इमारतों को बाहर से चमकाने के बरक्स शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार के लिए कितना कुछ किया गया है, यह बच्चों की पढ़ाई का स्तर देखने के बाद समझ में आता है! देश के बजट में रक्षा और शिक्षा के हिस्से में जितनी रकम आती है, उससे भी समझा जा सकता है कि सरकार के लिए सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था किस स्तर तक नजरअंदाज करने का मामला है!

बुलेट ट्रेन जैसी फिलहाल गैरजरूरी परियोजनाओं के लिए लाख करोड़ से ज्यादा रकम के लिए तुरंत हामी भर दी जाती है, लेकिन योग्य शिक्षकों की भर्ती और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर खर्च करने का सवाल शिक्षा के मद में राशि की कटौती की मार से दब जाता है! ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूलों के भरोसे शिक्षा हासिल करने का सपना पालने वाले कमजोर और वंचित सामाजिक तबकों के सामने कौन-सी तस्वीर बनती है!

खबरें फटाफट

देश

- बस्ती: 1 करोड़ के पुराने नोट बदलने जा रहे थे, 5 गिरफ्तार
- अमृतसर: 4 हेरोईन तस्करों को 20 वर्ष की कैद, 5 लाख जुर्माना
- छत्तीसगढ़ : 2 नक्सली गिरफ्तार
- गुजरात: 52 लाख की अवैध शराब बरामद
- पंजाब: पानी दलित व किसानों के मुद्दे पर अकाली, भाजपा व आप का वॉक आउट
- लुधियाना: 1 किलो हेरोईन के साथ 2 पकड़े
- अहमदाबाद: फैक्टरी का बॉयलर फटा, 1 की मौत, 4 घायल
- बनासकांठा: जीरे से भरा ट्रक लूटा
- आंध्र प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ेंगी: शाह
- उम्र ज्यादा हो गई, बीमार भी हूं, सजा कम दीजिए: लालू बोले जज से
- भगवान राम मंदिर बनाने का यही सही समय: भागवत
- राशन कार्ड से अब देश में कहीं भी ले सकेंगे राशन
- किसानों के लिए अन्ना आज से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे
- 20 आप विधायकों पर हाईकोर्ट का फैसला आज
- हैदराबाद: कचरे में मिले 1 लाख रु. महिला सफाई कर्मी ने लौटाए

पिंटू पटाखा

एक सफलता जो
आपको 'घमंडी' बना दे
उससे अच्छी वो गलती/हार है जो
आपको 'विनम्र' होने
को विवश करे।

प्रदेश

- कोटा: पति की हत्या में पत्नी व सास को उम्रकैद
- अहंकारी व्यक्ति अधिक दिन तक पद पर नहीं रहता: सीएम राजे
- एम्बुलेंस हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, पब्लिक परेशान
- अलवर: पानी के टैंकर से कुचलकर बच्ची की मौत
- भाजपा सरकार बजरी माफिया को पनपा रही: कांग्रेस

(शेष पेज 8 पर)

The Economist

विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में

रिसर्च... अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिभावान छात्रों को मिलने वाले कम नंबर या रेटिंग पर शोध किया और पाया कि इसमें जज भी लापरवाही कर जाते हैं।

आखिरी में आने वाले छात्रों को ही मिलते हैं ज्यादा अंक

किसी भी कक्षा या पाठ्यक्रम के छात्रों का आकलन उनके शैक्षणिक ज्ञान एवं दिमागी क्षमता के आधार पर होने के बाद ही विश्वविद्यालयों में उन्हें प्रवेश दिया जाता है। एथलीट का परीक्षण उसकी शारीरिक क्षमता के आधार पर होता है, तभी उसे मेडल मिलता है। इसी तरह शोध पत्रों का प्रकाशन कई वरिष्ठ एवं बुद्धिजीवी लोगों द्वारा उसकी समीक्षा के बाद किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया में मूल्यांकन करने के पहले मूल्यांकनकर्ता सीक्वेंस में देखते हुए पता करते हैं कि छात्र, एथलीट, शोधार्थी या अन्य ने जरूरी योग्यता का प्रदर्शन किया है या नहीं, उसके बाद वे मानकीकृत मानदंड लागू करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया में यही समझा जाता है कि सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन 'साइकोलॉजिकल साइंस' में प्रकाशित हाल के शोध में विपरीत बातें सामने आई हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉ. कीरन ओ'कोनोर एवं डॉ. अमार चीमा ने अपने शोध के दौरान पाया कि इस तरह की प्रक्रिया में ज्यादा बेहतर परिणाम उसके पक्ष में जाता है, जो उस प्रक्रिया में अंतिम दौर में आता है। वे यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि जब कोई मूल्यांकनकर्ता बार-बार एक ही प्रक्रिया में किसी का मूल्यांकन करता है, तो उन्हें महसूस होता है कि उनके लिए फैसला करना आसान है। अगर वाकई ऐसा होता है, तो उनके इसी प्रवाह या तौर-तरीके में वृद्धि होती है और अनजाने में ही मूल्यांकनकर्ता का अच्छा फैसला उनके पक्ष में ज्यादा जाता है जो आखिरी दौर में थे। यह शोध करने वाले डॉक्टरों ने अपने आइडिया का परीक्षण करने के लिए मशहूर रियलिटी शो 'डान्सिंग विद द स्टार्ट' के लगातार 20 शो देखे और वहां मौजूद जजों द्वारा अभ्यर्थियों को रेटिंग देने के तरीके को बारीकी से देखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्वविद्यालय के पिछले तीन सेमेस्टर में एक ही लेक्चरर द्वारा 1,358 विद्यार्थियों को दिए गए ग्रेडिंग का भी अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वर्ष बीतने के साथ डान्सिंग के स्कोर में भी बढ़ोतरी हुई। पहले 10 सेशन में दस में से 7.87 नंबर औसत रहे। उसके बाद के दस सेशन में दस में से 8.18 औसत नंबर रहे। यहां उन्होंने पाया कि जो ज्यादा प्रतिभाशाली डांसर थे, वे पहले सेशन के 10 या दूसरे सेशन के शुरुआती दौर में ही बाहर कर दिए गए। इस तरह 13 डांसर बाहर हो गए।

यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग की बात हो या किसी रियलिटी शो में स्कोर देने की, जैसे-जैसे दौर बीतता है जजों को अपना काम आसान लगने लगता है। ऐसे में कई बार प्रतिभावान अभ्यर्थी का नुकसान हो जाता है।

विद्वानों को विश्वविद्यालय में छात्रों को दी गई ग्रेडिंग में भी यही दिखाई दिया। ए ग्रेड की वैल्यू 4.0, बी ग्रेड की वैल्यू 3.0 और सी ग्रेड की वैल्यू 2.0 थी। छात्रों को दिए गए औसत ग्रेड के नंबर समय बढ़ने के साथ बढ़ते गए। कठिन विषय का औसत 3.37 से 3.57 हुआ जो पहले से 20 गुना कठिन विषयों में 3.70 तक पहुंचा। अन्य शब्दों में कहें तो विषयों में औसत ग्रेड बीप्लस से ए माइनस पर पहुंच गया। लेक्चरर के ग्रेड परीक्षण से यह पता चल गया कि उनके काम करने के तरीके में किस तरह बदलाव होता है। हालांकि, होना तो यह चाहिए था कि लगातार मूल्यांकन करने से उनकी प्रैक्टिस में सुधार होना था, जबकि यहां छात्रों की ग्रेडिंग में बढ़ोतरी हो रही थी।

शोधकर्ताओं ने पहले तीन वर्ष तक लेक्चररों और उनके विषयों पर गौर किया। उन्होंने पाया कि लेक्चरर अपने विषयों को पहले से ज्यादा समझने लगे थे। इस अवधि में उनके कार्य करने या ग्रेड देने की कार्यप्रणाली में वही सुधार आया, जो आना चाहिए था। एक बदलाव यह देखने को मिला कि जहां ग्रेड देने के लिए पहले टिक लगते थे, वह स्थान अब खाली थे, यानी वे संभलकर टिक लगाने लगे थे। अंततः डॉ. ओ'कोनोर और डॉ. चीमा ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने 518 लोगों को दस छोटी कहानियों का दस दिन में मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसमें भाग लेने वालों ने 1 यानी सबसे खराब और 10 यानी सबसे अच्छी के आधार पर रेटिंग दी। उनसे कहा गया था कि प्रत्येक मूल्यांकन के बाद वे अपनी रिपोर्ट दें और बताएं कि कितनी आसानी से, जल्दी और खुशनुमा रहकर उन्होंने मूल्यांकन किया। उनसे मूल्यांकन का अनुभव भी पूछा गया था।

जैसा कि अनुमान था, रेटिंग देने वालों ने बताया कि 10 दिन पूरे होने के अंतिम दौर में उन्होंने ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग दी थी। हालांकि, यह डान्सिंग स्कोर और विश्वविद्यालय के ग्रेड से अलग थी। डॉ. ओ'कोनोर और डॉ. चीमा ने यहां पता लगाया कि स्कोर बढ़ने क्यों लगता है। उन्हें अहसास हुआ कि कहानियों को रेटिंग देने वालों को बाद में वह काम आसान लगने लगा था। यहां डॉ. ओ'कोनोर और डॉ. चीमा का शोध सही साबित हुआ।

© 2016 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

9 विश्वविद्यालयों को राजभवन का नोटिस, भर्तियों में देरी पर मांगी रिपोर्ट

हर्ष खटाना | जयपुर

प्रदेश के 9 सरकारी विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्तियों में देरी हुई है। इसी के चलते राज्यपाल सचिवालय ने इन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगे है। राज्यपाल के दिशा-निर्देश पर राजभवन ने ये एक्शन लिया है। इन विश्वविद्यालयों में भर्तियों के मामले में शिकायतें आने और मामले में कोर्ट में फंसने या राज्य सरकार के स्तर पर लंबित रहने जैसी वजहों से भर्ती में देरी हुई है। इन विश्वविद्यालयों को जारी हो चुके हैं नोटिस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, आरयूएचएस जयपुर, कोटा विश्वविद्यालय और कोटा ओपन शामिल है।

नोटिस के मायने क्या : राजभवन ने इन विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजकर मंशा स्पष्ट कर दी है कि विश्वविद्यालय के कुलपति भर्तियों में बिलकुल लापरवाही नहीं बरते और गंभीरता से भर्तियों को अंजाम तक पहुंचाएं। इसी के चलते विश्वविद्यालयों के मुखियाओं को नोटिस भेजे गए है। उधर उच्च शिक्षा विभाग से भी इस मामले में पत्र भेजे जा चुके है।

इन चार विवि में स्थायी कुलपति नहीं, तीन में भर्तियों की रफ्तार प्रभावित

प्रदेश में चार विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति नहीं है। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों में भर्तियों पर असर पड़ा है। इसमें जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की भर्ती शामिल है। इसी तरह बीकानेर वेटरनरी यूनिवर्सिटी, अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी और जोधपुर की पुलिस यूनिवर्सिटी शामिल है। पुलिस यूनिवर्सिटी को छोड़कर शेष तीन में कुलपति पद की जिम्मेदारी दूसरे विश्वविद्यालयों के कुलपति बतौर कार्यवाहक के निभा रहे है।

कैमिस्ट्री के लिफाफे में निकला हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र

पेपर आउट मानकर परीक्षा निरस्त की

भरतपुर | महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की गलती से गुरुवार को हिंदी साहित्य का पेपर आउट हो गया। इसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। यह परीक्षा भी गुरुवार को ही तीसरी पारी में होनी थी। इससे करीब 9500 विद्यार्थी मानसिक तनाव में आ गए हैं। क्योंकि नई तिथि फिलहाल घोषित नहीं हुई है। लेकिन, विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी ही अप्रैल के दूसरे सप्ताह में निरस्त हुए पेपर की परीक्षा लिए जाने की बात कर रहा है। इससे पहले भी प्रश्नपत्रों के लिफाफे पर गलत तारीख प्रिंट होने की वजह से एक पेपर जल्दी खुल गया था। ब्रज विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में गुरुवार को दूसरी पारी में प्रथम वर्ष विज्ञान के कैमिस्ट्री के पहले पेपर की परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले जब एसआरपीजी नदबई, अग्रसेन कन्या कॉलेज बयाना, संस्कार कॉलेज नदबई और अग्रसेन विद्यापीठ रंजीत नगर में प्रश्न पत्रों के लिफाफे खोले गए तो उनमें हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र निकले।

स्कॉलरशिप और फेलोशिप

यूसीडी स्पायर डॉक्टर स्कॉलरशिप, 2018

किसके लिए - आयरलैंड में रहकर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी करने के इच्छुक भारतीय पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए।

योग्यता - बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ पोस्टग्रेजुएट डिग्री की हो।

राशि - पूरी फीस व रख-रखाव हेतु 14 हजार यूरो की राशि प्रतिवर्ष चार साल तक दी जाएगी।

अंतिम तिथि - 30 मार्च, 2018

www.b4s.in/DBL/USD1

जीईएसएस सेंटर फॉर डॉक्टोरल स्टडीज़ इन इकोनॉमिक्स स्कॉलरशिप

किसके लिए - यूनिवर्सिटी ऑफ मन्हेम, जर्मनी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी (दो साल के कोर्स व तीन साल के रिसर्च) करने के इच्छुक ग्रेजुएट व पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए।

योग्यता - मन्हेम यूनिवर्सिटी के द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में पीएचडी हेतु दाखिला ले चुके छात्र।

राशि - 1200 यूरो (प्रतिमाह) जीवन भत्ता व 1200 यूरो की राशि प्रतिमाह पढ़ाई के लिए दी जाएगी।

अंतिम तिथि - 31 मार्च, 2018

www.b4s.in/DBL/DSI1

आईआईएडी स्कॉलरशिप 2018-19

किसके लिए - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के अंडरग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम में आवेदन करने वाले 12वीं पास छात्र आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए।

योग्यता - किसी भी स्ट्रीम में 70% प्रतिशत अंको के साथ 12वीं पास करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं।

राशि - ट्यूशन फीस में कुछ प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

अंतिम तिथि - 31 मार्च, 2018

www.b4s.in/DBL/IS57

8वीं साइंस के पेपर में छात्रों को मिलेंगे बोनस अंक

बीकानेर | 8वीं बोर्ड परीक्षा में साइंस विषय के प्रश्न-पत्र में स्टूडेंट्स को चार अंक बोनस दिए जाएंगे। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर के समन्वयक ने इस संबंध में राज्य के सभी डाइट प्राचार्य को निर्देश जारी किए है। परीक्षा के तहत 20 मार्च को साइंस विषय का पेपर हुआ था। जिसके प्रश्न संख्या 23 के अथवा के भाग में कुछ भाग छापने से रह गया। इससे चार अंक का कार्य प्रभावित हुआ है। विभाग के विशेषज्ञों की कमेटी के निर्णयानुसार जिस छात्र ने इस प्रश्न को हल किया है उन्हें चार अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। डाइट प्राचार्यों को कॉपी जांचने वाले परीक्षक को बोनस अंक देने के लिए पाबंद करने के निर्देश भी दिए गए है।

9वीं-11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से

टाइम टेबल घोषित, पेपर वितरण 11 अप्रैल को

एजुकेशन रिपोर्टर | बीकानेर

जिला समान परीक्षा योजना के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है।

परीक्षा संयोजक मोहर सिंह यादव ने बताया कि परीक्षा दो पारी में होगी। प्रथम पारी का समय सुबह 8.30 से दोपहर 11.45 बजे और दूसरी पारी का दोपहर 12.15 से 3.30 बजे तक रहेगा। 9वीं कक्षा की सभी परीक्षाएं पहली पारी में होगी। जबकि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं विषयवार दोनों पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान अक्षय तृतीया, आंबेडकर जयंती, परीक्षा अंतराल और दो रविवार सहित कुल पांच छुट्टियां रहेगी। संस्था प्रधानों को प्रश्न-पत्रों का वितरण परीक्षा से दो दिन पूर्व 11 अप्रैल को राजकीय चौपड़ा स्कूल से किया जाएगा। परीक्षा संयोजक ने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी संस्था प्रधानों को निर्धारित तिथि 11 अप्रैल को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक प्रश्न-पत्रों का वितरण होगा। जबकि प्राइवेट स्कूलों के प्रश्न-पत्र पूर्व की तरह की संबंधित संकुल विद्यालय में रहेंगे। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले संबंधित प्राइवेट स्कूल के संस्था प्रधान प्रश्न-पत्र हासिल कर सकेंगे। गौरतलब है कि 5वीं कक्षा को छोड़कर पहली से 7वीं कक्षा की परीक्षाएं भी इसी अवधि में होगी। जिनके प्रश्न-पत्र स्कूली स्तर पर ही तैयार होंगे।

8वीं विज्ञान पेपर में 4 बोनस अंक मिलेंगे

उदयपुर | प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (8वीं) के विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र में विद्यार्थियों को 4 अंक बोनस दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 23 के अथवा भाग में कुछ हिस्सा छपने से रह गया था। जिन छात्रों ने इस प्रश्न को हल किया है, उन्हें 4 अंक बोनस में दिए जाएंगे।

राज्यकर्मियों का डीए 2% बढ़ेगा

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

सरकार राज्य कर्मियों व पेंशनर्स का डीए 2 प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर फाइल सीएमओ भेजी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। बढ़े हुए डीए के आदेश शुक्रवार को जारी होंगे। सातवां वेतनमान जारी होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत हो चुका है। अब यह बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ाया था। केंद्र में इजाफे के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से पहले ही मिलेगा अगली कक्षा में प्रवेश

अस्थाई प्रवेश के निर्देश जारी, शिक्षण कार्य होगा नियमित

बीकानेर | सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के लिए 5वीं, 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं दे चुके स्टूडेंट्स को रिजल्ट आने से पहले ही अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश देकर शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।

वहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी परीक्षा समाप्ति के बाद रिजल्ट घोषित होने से पहले ही सरकारी स्कूलों में अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है।

8वीं-10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी। जबकि 5वीं की बोर्ड परीक्षा 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगी। वहीं स्कूली स्तर पर अन्य कक्षाओं के होम एग्जाम 13 से 25 अप्रैल तक होंगे। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने समय निर्धारित किया है। 8वीं-10वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होते ही इन कक्षाओं के स्टूडेंट्स को 27-28 मार्च से आगामी कक्षा में प्रवेश देकर शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। जबकि 5वीं बोर्ड के अभ्यर्थियों को अस्थाई प्रवेश 16 अप्रैल से मिलेगा।

राज्य के 281 सरकारी स्कूल अपग्रेड, नए सत्र से मिलेगा प्रवेश

106 सैकंडरी स्कूल सीनियर सैकंडरी और 175 मीडल स्कूल सैकंडरी में क्रमोन्नत

बीकानेर | राज्य में 281 ग्राम पंचायतों के 106 सैकंडरी स्कूलों को सीनियर सैकंडरी और 175 उच्च प्राथमिक स्कूल को सैकंडरी में क्रमोन्नत किया गया है।

अपग्रेड हुए इन स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2018-19 से 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश शुरू होंगे। वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा प्रवेश शिक्षा सत्र 2019-2020 से होंगे। नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक स्कूलों में तीन ऐच्छिक विषय व्याख्याता के पद मिलेंगे। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा में अनिवार्य अंग्रेजी और हिंदी विषय बच्चों को सैकंड ग्रेड टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अपग्रेड हुए सीनियर सैकंडरी स्कूलों की सूची में सबसे अधिक चूरू और झुंझनू के 14-14 स्कूल और सबसे कम टोंक और बूंदी का एक-एक स्कूल शामिल है। वहीं बीकानेर जिले के 5 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। अपग्रेड हुए सैकंडरी स्कूलों की सूची में सबसे अधिक 47 स्कूल जोधपुर और सबसे कम एक-एक स्कूल कोटा, करौली, सीकर और भरतपुर का शामिल है। बीकानेर के 23 स्कूल उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए है।

सीबीएसई ने जारी की सूचना

नेट में भी आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त

कासं/नवज्योति, अजमेर

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) के आवेदन के समय आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी कर दी है। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो आधार नहीं होने से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। मालूम हो कि जूनियर रिसर्च फैलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए यह परीक्षा 8 जुलाई को होगी। परीक्षा के ऑनलाइन

आवेदन 6 मार्च से शुरू हो गए हैं। बोर्ड ने इसके लिए आधार की अनिवार्यता को लागू किया था। इस संबंध में फरवरी के तीसरे सप्ताह में ही वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दी गई थी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड नहीं था, वे परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

अब उलझन समाप्त

8 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद बोर्ड ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट (नीट यूजी) के लिए आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। जिसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी। लेकिन नेट के लिए इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे। जिससे अभ्यर्थी उलझन में थे। बोर्ड ने हाल ही में सूचना जारी कर कहा है कि आवेदक, पहचान के प्रमाण के रूप में आधार या आधार नामांकन या राशनकार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता संख्या या अन्य कोई वैध सरकारी पहचान-पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र आदि का उपयोग कर सकते हैं।

5 अप्रैल तक आवेदन

आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। जबकि अभ्यर्थी 6 अप्रैल तक ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करा सकेंगे। गौरतलब है कि परीक्षा के दौरान इस बार तीन की जगह दो पेपर होंगे।

बच्चों को बोनस के रूप में मिलेंगे चार अंक

प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के नियम में खामी, मार पड़ रही बेरोजगारों पर

वहां नौकरियों में बाहरी का कोटा तय, यहां नहीं

सामान्य वर्ग में बाहरी राज्यों के लिए आवेदन में किसी तरह की बंदिश नहीं, अन्य राज्यों में बाहरी के लिए 15% कोटा तय

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर प्रदेश में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार जो भर्तियां निकाल रही हैं, उनमें भी बाहरी प्रदेशों के युवा कब्जा जमा रहे हैं। प्रदेश में बाहरी राज्यों के लिए कोटा तय नहीं है। अजा-जजा व अन्य वर्गों के आरक्षण के बाद सामान्य वर्ग के लिए बचे पूरे पदों पर बाहरी राज्यों के युवा आवेदन कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। शिक्षक, एलडीसी व कर्मचारी वर्ग की अन्य नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं का प्रतिशत 20-25 प्रतिशत तक है। जबकि पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी आदि पड़ोसी राज्यों में बाहरी प्रदेशों का कोटा तय किया हुआ है।

रीट 2017 : 9 लाख में से पड़ोसी राज्यों के 2.5 लाख

11 फरवरी को आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट 2017 में 9 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें से करीब 2.5 लाख युवा हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों के थे। इन राज्यों के युवा नौकरी पाने के बाद अपने प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए जिलों में ही पोस्टिंग ले लेते हैं। हरियाणा के युवा अलवर, पंजाब के गंगानगर जिलों व गांवों में जुगत से पोस्टिंग करवा लेते हैं।

पंजाब-हरियाणा में 15 फीसदी पदों पर ही प्रवेश

पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को सीमित पदों पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। पंजाब व हरियाणा में केवल 15 फीसदी पद बाहरी राज्यों के तय हैं। शेष बचे 85 फीसदी पदों पर केवल संबंधित राज्य के युवाओं के लिए ही आरक्षित हैं। अगर आवेदक का वर्तमान निवास संबंधित प्रदेश का हुआ, मगर मूल निवास किसी अन्य राज्य का, तो भी उसे 15 फीसदी पदों तक ही मौका दिया जा रहा है।

“ प्रदेश में हमें ही प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारों की फौज है। फिर भी बाहर के लोग आकर नौकरी पा रहे हैं।

चित्रांश शर्मा, बेरोजगार अभ्यर्थी

एमपी में बाहरी राज्यों के युवाओं का चयन नहीं

हाल ही में मध्यप्रदेश में आयोजित हुई पटवारी परीक्षा में तो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया गया। विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया गया कि केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। वहीं अन्य भर्तियों में बाहरी राज्यों के युवा 25 साल की उम्र तक ही भाग ले सकते हैं।

शिक्षा में भी पड़ोसी राज्यों में कोटा तय

नौकरी के साथ शिक्षा में भी पड़ोसी राज्यों ने बाहरी प्रदेशों के लिए कोटा तय कर रखा है। पीएचडी, मेडीकल, इंजीनियरिंग सहित सभी पाठ्यक्रमों में बाहरी राज्यों व एनआरआई छात्रों के लिए केवल 15 फीसदी सीटें ही हैं।

राज्य में तय हो सीमा

“ अन्य राज्यों में वहां के लोकल अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका दिया जाता है। जबकि राजस्थान में यहां के बेरोजगारों के लिए मौके कम हैं। इसलिए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सीमा तय होनी चाहिए।

उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ

समायोजित शिक्षकों को एसीपी का लाभ देने की मांग

अजमेर। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डीडेल को ज्ञापन सौंपकर समायोजित अध्यापकों को एसीपी का लाभ देने की मांग की है। निदेशक ने महासंघ प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण भरोसा देते हुए कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक इनके कैडर को बदलकर समस्त परिलाभ दिया जाएगा तथा वर्तमान में वसूली नहीं होगी। संगठन ने पातेय वेतन वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाध्यापक को पदोन्नति का लाभ देने की मांग की । बाद में जिला कलेक्टर गौरव गोयल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कांति कुमार शर्मा, दिनेश शर्मा, उमेश शर्मा, मुकेश कांसट, कमला मिश्रा, सुशीला सोनी, महेंद्र बुन्देल, प्रकाश बुन्देल, निशा बंसल, गायत्री देवी, मंजरी पारीक सहित अन्य उपस्थित थे।

दिसंबर से पहले पांच हजार स्कूली व्याख्याताओं की होगी भर्ती

अजमेर/जयपुर। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की कवायद शुरू कर दी है। विभाग द्वारा दिसंबर से पहले स्कूल शिक्षा के पदों की भर्ती प्रकिया पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर की ओर से शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया होगी। स्कूल व्याख्याता के पदों पर 4 हजार 988 में हिन्दी 1025, पॉलिटिकल साइंस 955, हिस्ट्री 753, ज्योग्राफी 782, अंग्रेजी 304, संस्कृत 136, फिजिक्स 187, कैमिस्ट्री 160, बायोलोजी 166, मैथ्स 193, कॉमर्स 118 और इकोनोमिक्स 109 सम्भावित पद है।

374 शिक्षकों का स्थाईकरण, 61 को दी नियुक्ति

अजमेर। जिला परिषद में गुरुवार को आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक में तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2012 प्रथम एवं द्वितीय स्तर के 374 शिक्षकों के स्थाईकरण और तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित द्वितीय स्तर अंग्रेजी विषय के 61 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। जिला प्रमुख वंदना नोगिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीईओ अरूण गर्ग, एसीईओ भगवंत सिंह राठौड़, एसीईओ प्रारम्भिक शिक्षा श्यामलाल सांगावत, जिला कलक्टर प्रतिनिधि के रूप में जिला रसद अधिकारी संजय माथुर एवं कार्यालय अधीक्षक योगेश सिंघल उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि ये शिक्षक लम्बे समय से स्थाईकरण की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई बार जिला प्रमुख, जिला कलक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी दिए थे।

स्थाईकरण को लेकर हुई बैठक में जिला प्रमुख एवं अन्य अधिकारी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग

विभिन्न परीक्षाओं की तिथियां घोषित

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने खान एवं भू विज्ञान विभाग, नगर नियोजन विभाग और कृषि विभाग के विभिन्न पदों की कम्प्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट पद्धति से ऑनलाइन संवीक्षा परीक्षा की तिथियां घोषणा कर दी हैं। यह परीक्षाएं 23 से 25 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।

यह रहेगा कार्यक्रम

दिनांक	विषय	समय
23 अप्रैल	केमिस्ट - खान एवं भू विज्ञान विभाग,	प्रात:10 से 12 बजे तक
23 अप्रैल	टाउन प्लानिंग असिस्टेंट -टीपीए, नगर नियोजन विभाग	प्रात:10 से 12 बजे तक
23 अप्रैल	एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, हॉर्टीकल्चर, कृषि विभाग	दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक
24 अप्रैल	जियोलॉजिस्ट - खान एवं भूविज्ञान विभाग	प्रात: 10 से 12 बजे तक
24 अप्रैल	सांख्यिकी अधिकारी - कृषि विभाग	दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक
25 अप्रैल	सहायक कृषि अधिकारी टीएसपी एरिया, कृषि विभाग	पेपर - 1 प्रात: 10 से 12 बजे तक पेपर- 2 दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक

अगले माह से ग्राम साथिनों के मानदेय में 900 रुपए की वृद्धि

कासं/अजमेर।

महिला एवं बाल विकास विभाग में मानदेय कर्मचारियों के रुप में कार्यरत ग्राम साथिनों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मानदेय बढ़ोत्तरी की मांग को हरी झण्डी मिलने के बाद गुरुवार को भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। अब साथिनों को नए वित्तीय वर्ष से नौ सौ रुपए बढ़कर मानदेय मिल सकेगा।

विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के बाद से ही इनके द्वारा भी बढ़ोत्तरी के प्रयास किए जा रहे थे। राज्य सरकार ने गत माह ही इनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें 900 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में मानदेय के रुप में उन्हें दो हजार 400 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अब नौ सौ रुपए की बढ़ोत्तरी के बाद 3 हजार 300 रुपए का भुगतान जाएगा। जिले की 9 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों पर 282 ग्राम साथिनों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से मौजूदा समय में 248 कार्यरत है, जबकि 34 पद रिक्त चल रहे हैं। यह पंचायत स्तर पर ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभान्वित होने के लिए जागरुक करने का काम करती है।

बोर्ड परीक्षा खत्म होने के दूसरे ही दिन से नई कक्षा

छात्रों को आगामी कक्षाओं में दिया जाएगा अस्थाई प्रवेश

जयपुर @ पत्रिका. राज्य में बोर्ड परीक्षाएं अंतिम चरण में हैं। 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के दूसरे ही दिन से अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस सम्बंध में शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा खत्म होने व नई कक्षा शुरू होने के बीच एक दिन का समय भी नहीं मिलेगा। इधर, शिक्षक संगठनों ने इस आदेश को गैर व्यवहारिक बताया है। वहीं इस दौरान 13 से 25 अप्रेल तक जिला समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 1 से 4,6,7,9 व 11 की वार्षिक परीक्षाएं भी होगी। इनका परिणाम 30 अप्रेल को घोषित किया जाएगा तथा आगामी कक्षाएं 1 मई शुरू होंगी।

यूं शुरू होगा नया शिक्षा सत्र

- 8वीं कक्षा की परीक्षा 26 मार्च को खत्म होंगी। 9वीं कक्षा 27 मार्च से शुरू हो जाएगी।
- 10वीं कक्षा की परीक्षा 27 मार्च को खत्म होगी। वहीं इनके छात्रों की आगामी कक्षा 28 मार्च से शुरू हो जाएगी।
- 5वीं की बोर्ड परीक्षा 13 अप्रेल को समाप्त होगी तथा छठी कक्षा 16 अप्रेल से शुरू हो जाएंगी।

इनका कहना है

यह आदेश गैर व्यावहारिक हैं। इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। शिक्षक स्थानीय परीक्षा कराएंगे या नई कक्षाओं को का संचालन करेंगे। साथ ही स्थानीय परीक्षाओं का परिणाम भी जारी करना होगा। वहीं विद्यार्थियों को भी राहत नहीं मिलेगी।

विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

सीबीएसई की सप्लीमेंट्री और श्रेणी सुधार परीक्षा जुलाई में

अजमेर. सीबीएसई की बारहवीं और दसवीं की सप्लीमेंट्री और श्रेणी सुधार परीक्षा जुलाई में होगी। वार्षिक परीक्षाएं खत्म होने और मई में परिणाम जारी होंगे। इसके बाद विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे।

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं जारी हैं। अजमेर, नई दिल्ली, इलाहाबाद, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी और पंचकुला रीजन में करीब 28 लाख विद्यार्थी मुख्य परीक्षाएं दे रहे हैं। इनके परिणाम मई में जारी होंगे। प्रतिवर्ष मुख्य परीक्षा में कम नंबर आने पर विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री और श्रेणी सुधार में शामिल किया जाता है।

20 लाख तक ग्रेच्युटी करमुक्त करने को मंजूरी

नई दिल्ली @ पत्रिका . संसद ने गुरुवार को ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया । पारित होने के बाद सरकार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारियों की मौजूदा दस लाख की कर मुक्त ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा 20 लाख रुपए करने में सक्षम होगी। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जिसे बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

60 फीसदी हाजिरी जरूरी

पांचवीं बोर्ड परीक्षा 5 से, 4 किमी. दूर तक बनाए केंद्र

जयपुर @ पत्रिका. 12वीं, 10वीं व आठवीं कक्षा के बाद अब 5 अप्रेल से पांचवीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा 11 अप्रेल तक चलेगी। इस दौरान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन आदि चार विषयों की परीक्षा होगी। वहीं संस्कृत विद्यालयों व मदरसों की परीक्षा 13 अप्रेल तक चलेगी। 13 को संस्कृत व उर्दू की परीक्षा होगी।

इस बार पांचवीं कक्षा के बच्चे भी अन्य बोर्ड कक्षाओं की तरह स्कूल से बाहर परीक्षा केंद्र आएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय में आदर्श या उत्कृष्ट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जहां आदर्श या उत्कृष्ट स्कूल नहीं हैं, वहां चार किमी दूरी तक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 60 फीसदी हाजिरी होना जरूरी है। वहीं बीमारी की स्थिति में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। लगातार 45 दिन अनुपस्थित रहने पर ड्रॉप आउट मानकर उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। 86 फीसदी व इससे अधिक उपस्थिति पर 5 अंक दिए जाएंगे।

एमपैट 2017 की परीक्षा 22 को

जयपुर @ पत्रिका. राजस्थान विवि में पीएचडी-एमफिल की प्रवेश परीक्षा एमपैट-2017, 22 अप्रेल को होगी। एमपैट से 38 विभिन्न विषयों में एमफिल व पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 22 को सुबह 11 बजे से 2.30 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 3100 छात्र प्रविष्ट होंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 अप्रेल विवि की वेबसाइट से अपलोड किए जा सकेंगे। विषय व परीक्षा केंद्र वार जानकारी भी तभी से वेबसाइट से देखी जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 78 पदों पर भर्ती

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (एससीआई) ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर अटेंडेंट के कुल 78 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 01 मार्च, 2018 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 15 अप्रैल, 2018

योग्यता : किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होने के अलावा संबंधित ट्रेड का ज्ञान होने के साथ ही कार्यानुभव होना जरूरी है। जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के लिए ड्राइविंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिशियन, कार्पेंटरी आदि और चैंबर अटेंडेंट के लिए हाउस कीपिंग वर्क, केटरिंग वर्क आदि ट्रेड का ज्ञान होना जरूरी।

चयन प्रक्रिया : लिखित परीक्षा में मेरिट अंकों और स्किल टैस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थी को चुना जाएगा।

नोटिफिकेशन देखें : http://supremecourtofindia.nic.in/pdf/recruitment/recruitement20032018.pdf

अधिक जानकारी के लिए देखें: http://supremecourtofindia.nic.in/

डेट रिमाइंडर

- **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर**
  पद : पर्सनल असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ व अन्य पद (04 पद)
  आवेदन की अंतिम तिथि: 02 अप्रैल, 2018
- **नेशनल टेक्नीकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन**
  पद : साइंटिस्ट-बी (62 पद)
  आवेदन की अंतिम तिथि: 14 अप्रैल, 2018
- **कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन** (42 पद)
  पद : लैबोरेट्री टेक्नीशियन
  आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2018
- **ऑयल इंडिया लिमिटेड**
  पद : जूनियर असिस्टेंट आदि पद (06 पद)
  आवेदन की अंतिम तिथि: 25 अप्रैल, 2018
- **सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन**
  पद : सब-इंस्पेक्टर (10 पद)
  आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल, 2018
- **ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल** (43 पद)
  पद : ट्यूटर/ डेमॉन्सट्रेटर
  वॉक इन इंटरव्यू की तिथि : 05 व 06 अप्रैल, 2018
- **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग**
  पद : ईडीपी सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट (44 पद)
  आवेदन की अंतिम तिथि: 11 मई, 2018
- **मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.** (10 पद)
  पद : एग्जीक्यूटिव ट्रेनी
  आवेदन की अंतिम तिथि: 08 मई, 2018

अधूरे प्रश्न के मिलेंगे बोनस अंक

जयपुर. चाकसू. आठवी बोर्ड परीक्षा में गत मंगलवार को हुए विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र में आए एक अधूरे सवाल के विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर ने गुरुवार को समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को आदेश जारी कर दिए। प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 23 में दूसरे विकल्प का प्रश्न अधूरा था। पत्रिका ने समाचार प्रकाशित कर मामले को उजागर किया था। उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए।

रक्षा मत्रालय

शहीदों के बच्चों का शिक्षा खर्च उठाएगी सरकार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली . सरकार शहीदों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। रक्षा मंत्रालय ने शहीदों के बच्चों के लिए 10 हजार रुपए तक सीमा को हटा दिया है। इसके साथ ही शिक्षा खर्च पर से सीमा हटाने का आदेश दिया है। बीते साल सरकार ने यह रियायत 10 हजार तक सीमित रखी थी। इससे सेना में भारी असंतोष हो गया था। यह मदद सिर्फ सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शैक्षिक संस्थाओं, सैनिक स्कूलों, केंद्र-राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों या फिर वित्त पोषित संस्थाओं में ही मिलेगी।

छात्राओं का आरोप, परीक्षा केंद्र पर पुरुष शिक्षक करते हैं चैकिंग

राजस्थान विवि. के परीक्षा केंद्र पर लगे गंभीर आरोप

परीक्षार्थियों ने कुलपति से की शिकायत

प्रशासन ने बताया कॉलेजों के बीच आपसी रंजिश का मामला

डेली न्यूज

जयपुर ▷ 22 मार्च

राजस्थान विश्वविद्यालय के चाकसू स्थित एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में कई परीक्षार्थी गुरुवार को राज. विवि पहुंचे और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। परीक्षार्थियों ने ज्ञापन में सेंटर बदलने की मांग की है।

परीक्षार्थियों में शामिल एक छात्रा ने बताया कि चाकसू स्थित कस्तूरी देवी महाविद्यालय में पढ़ रही है। उनकी कॉलेज का सेंटर मानव पीजी महाविद्यालय में आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परीक्षा केंद्र के प्रबंधन ने एडमिट कार्ड की सेंटर कॉपी पर उनके नंबर ले लिए और उसके बाद से ही लड़कियों के पास लगातार फोन आ रहे हैं। छात्रा का आरोप है कि कॉलेज के पुरुष स्टाफ की ओर से उनकी बार-बार चैकिंग की जाती है।

पेपर पूरा नहीं करने देने का भी आरोप

छात्रों ने आरोप लगाया कि सेंटर प्रबंधन तय समय से आधे घंटे पहले उत्तर पुस्तिकाएं ले लेता है और पेपर पूरा नहीं करने देते। परीक्षार्थियों का आरोप है कि जब वे शिक्षकों की इन हरकतों का विरोध करते हैं तो उन्हें नकल में फंसाने की धमकी दी जाती है। छात्रनेता हेमंत विजय ने बताया कि मामले में शुक्रवार को चाकसू एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

शिकायत मिली है। मामला महाविद्यालयों की रंजिश का लग रहा है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही यूनिवर्सिटी की टीम परीक्षा केंद्र का भी निरीक्षण करेगी।

डॉ. वीके गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक,
राजस्थान विश्वविद्यालय

किसी छात्रा के पास फोन आया है तो सबसे पहले उस नंबर के आधार पर मामला दर्ज कराना चाहिए। जिस कॉलेज के छात्रों का हमारे सेंटर आया है, उनका सेंटर पहले दूसरी कॉलेज में आता था, जहां नकल कराई जाती थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन को शिकायत दी थी। प्रशासन ने सेंटर को उस कॉलेज से बदल हमारी कॉलेज में कर दिया। किसी कॉलेज से रंजिश नहीं है।

विकेश खोलिया, निदेशक
मानव पीजी कॉलेज, चाकसू

बोर्ड परीक्षा के अगले दिन शुरू होंगी कक्षाएं, शिक्षकों का विरोध

डेली न्यूज, जयपुर ▷ 22 मार्च

8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही अगले दिन से फिर कक्षाएं शुरू होंगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कक्षा 6, नौ और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने की तारीख भी तय हो चुकी है। इस दौरान 12वीं व पांचवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा व अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा होगी। शिक्षक संगठनों ने आदेश को गैर व्यवहारिक बताया। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि आदेश गैर व्यावहारिक है। शिक्षक स्थानीय परीक्षा कराएंगे या उनके रिजल्ट जारी करेंगे। इसी बीच कक्षाओं का संचालन होना मुश्किल है।

आरपीएससी : सदस्यों के पद खाली, सरकार पर निगाहें

डेली न्यूज

अजमेर ▷ 22 मार्च

दूसरे महकमों में भर्तियां करने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपनी स्थिति खराब है। एक तरफ आयोग ने कार्मिक विभाग से 58 पद मांगे हैं, वहीं यहां तीन सदस्यों के पद खाली हैं। सरकार ने न सदस्यों की नियुक्ति और न नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की इजाजत दी है।

वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा का गठन हुआ। इसका कार्य निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्तें 1963, राजस्थान लोक सेवा आयोग (शर्तें एवं प्रक्रिया का मान्यकरण अध्यादेश -1975, नियम-1976) के तहत किया गया। पहले आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते थे। कांग्रेस राज में 2012-13 में सात सदस्यीय बनाया गया। अभी डॉ. आर. डी. सैनी, राजकुमारी गुर्जर, सुरजीत लाल मीणा और के. आर. बागड़िया ही सदस्य हैं। तत्कालीन सदस्य हरिकिशन खींचड़, श्यामसुंदर शर्मा (बाद में अध्यक्ष बने) का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने कोई सदस्य नियुक्त नहीं किया है।

ऑनलाइन संवीक्षा परीक्षा 23 अप्रेल से

डेली न्यूज, अजमेर। आरपीएससी के तत्वावधान में खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नगर नियोजन विभाग एवं कृषि के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन संवीक्षा परीक्षा होगी। कम्प्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट 23 से 25 अप्रेल तक चलेंगे।

संवीक्षा परीक्षा ऑनलाइन कम्प्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट पद्धति से होगी। इसके तहत 23 अप्रेल को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक केमिस्ट (खान एवं भू-विज्ञान विभाग) स्क्रीनिंग टेस्ट-2015 और टाउन प्लानिंग असिस्टेंट (नगर नियोजन विभाग)-2015 की ऑनलाइन संवीक्षा परीक्षा होगी। इसी दिन दोपहर 2 से 4 बजे तक कृषि अनुसंधान अधिकारी-उद्यानिकी (कृषि विभाग) स्क्रीनिंग टेस्ट-2015 का आयोजन होगा।

24 अप्रेल को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक भूगर्भ शास्त्र (खान एवं भू-विज्ञान विभाग) स्क्रीनिंग टेस्ट 2015 और दोपहर 2 से 4 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) स्क्रीनिंग टेस्ट-2015 का आयोजन होगा। इसी तरह 25 अप्रेल को सहायक कृषि अधिकारी (टीएसपी क्षेत्र) कृषि विभाग स्क्रीनिंग टेस्ट-2016 का पेपर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पेपर दोपहर 2 से 4 बजे तक होगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं।

अध्यक्ष भी 41 दिन के

अध्यक्ष डॉ. राधेश्याम गर्ग का कार्यकाल 2 मई को खत्म होगा। वे अब 41 दिन ही काम कर पाएंगे। आयोग के नियमानुसार अध्यक्ष और सदस्य 62 वर्ष तक ही रह सकते हैं। डॉ. गर्ग 2 मई को 62 वर्ष के हो जाएंगे। पिछले साल तत्कालीन अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को कामकाज नहीं सौंपा गया था।

प्रमुख शिक्षा सचिव सहित तीन को अवमानना नोटिस

डेली न्यूज, जयपुर। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी शिक्षक को वरिष्ठता सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और भीलवाड़ा जिला परिषद के सीईओ को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश डालचंद की अवमानना याचिका पर दिए। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 13 नवंबर को आदेश जारी कर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2012 में चयनित याचिकाकर्ता शिक्षक को वरिष्ठता सहित अन्य परिलाभ देने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं की गई। ऐसे में अवमाननाकर्ता अधिकारियों को अदालती आदेश की अवमानना करने पर दंडित किया जाए।

प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के नियम में खामी, मार पड़ रही बेरोजगारों पर

वहां नौकरियों में बाहरी का कोटा तय, यहां नहीं

सामान्य वर्ग में बाहरी राज्यों के लिए आवेदन में किसी तरह की बंदिश नहीं, अन्य राज्यों में बाहरी के लिए 15% कोटा तय

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर प्रदेश में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार जो भर्तियां निकाल रही हैं, उनमें भी बाहरी प्रदेशों के युवा कब्जा जमा रहे हैं। प्रदेश में बाहरी राज्यों के लिए कोटा तय नहीं है। अजा-जजा व अन्य वर्गों के आरक्षण के बाद सामान्य वर्ग के लिए बचे पूरे पदों पर बाहरी राज्यों के युवा आवेदन कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। शिक्षक, एलडीसी व कर्मचारी वर्ग की अन्य नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं का प्रतिशत 20-25 प्रतिशत तक है। जबकि पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी आदि पड़ोसी राज्यों में बाहरी प्रदेशों का कोटा तय किया हुआ है।

रीट 2017 : 9 लाख में से पड़ोसी राज्यों के 2.5 लाख

11 फरवरी को आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट 2017 में 9 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें से करीब 2.5 लाख युवा हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों के थे। इन राज्यों के युवा नौकरी पाने के बाद अपने प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए जिलों में ही पोस्टिंग ले लेते हैं। हरियाणा के युवा अलवर, पंजाब के गंगानगर जिलों व गांवों में जुगत से पोस्टिंग करवा लेते हैं।

पंजाब-हरियाणा में 15 फीसदी पदों पर ही प्रवेश

पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को सीमित पदों पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। पंजाब व हरियाणा में केवल 15 फीसदी पद बाहरी राज्यों के तय हैं। शेष बचे 85 फीसदी पदों पर केवल संबंधित राज्य के युवाओं के लिए ही आरक्षित हैं। अगर आवेदक का वर्तमान निवास संबंधित प्रदेश का हुआ, मगर मूल निवास किसी अन्य राज्य का, तो भी उसे 15 फीसदी पदों तक ही मौका दिया जा रहा है।

> प्रदेश में हमें ही प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारों की फौज है। फिर भी बाहर के लोग आकर नौकरी पा रहे हैं।

चित्रांश शर्मा, बेरोजगार अभ्यर्थी

एमपी में बाहरी राज्यों के युवाओं का चयन नहीं

हाल ही में मध्यप्रदेश में आयोजित हुई पटवारी परीक्षा में तो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया गया। विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया गया कि केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। वहीं अन्य भर्तियों में बाहरी राज्यों के युवा 25 साल की उम्र तक ही भाग ले सकते हैं।

शिक्षा में भी पड़ोसी राज्यों में कोटा तय

नौकरी के साथ शिक्षा में भी पड़ोसी राज्यों ने बाहरी प्रदेशों के लिए कोटा तय कर रखा है। पीएचडी, मेडीकल, इंजीनियरिंग सहित सभी पाठ्यक्रमों में बाहरी राज्यों व एनआरआई छात्रों के लिए केवल 15 फीसदी सीटें ही हैं।

राज्य में तय हो सीमा

> अन्य राज्यों में वहां के लोकल अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका दिया जाता है। जबकि राजस्थान में यहां के बेरोजगारों के लिए मौके कम हैं। इसलिए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सीमा तय होनी चाहिए।

उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ

EDUCATION NEWS GROUP

आदर्श
शिक्षक
राजस्थान

EDU. NEWS GROUP

EGURUKULRAJASTHAN

एजुकेशन न्यूज ग्रुप